भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3514

उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

स्कूल में कंप्यूटर साक्षरता के लिए नीति

†3514. **श्री ईश्वरस्वामी के**.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में स्कूली बच्चों में कंप्यूटर साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कोई विशिष्ट नीति है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्कूली बच्चों में कंप्यूटर साक्षरता का राज्य-वार कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तमिलनाडु राज्य के विशेष संदर्भ में ऐसे अध्ययनों/सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ)**:** शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासन के अधीन हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 अपने अध्याय 23 और 24 में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा तथा आधारभूत समकालीन डिजिटल साक्षरता सहित इसके समतामूलक उपयोग पर अत्यधिक बल देती है। एनईपी 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह शिक्षा क्षेत्र को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक समग्र, लचीले और बहु-विषयक क्षेत्र में बदलने की परिकल्पना करती है।

शिक्षा मंत्रालय देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी और डिजिटल पहलों को लागू करता है। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

तमिलनाडु राज्य ने सूचित किया है कि सभी सरकारी माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं- जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6,995 स्कूल और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 6,223 स्कूल शामिल हैं, 22,931 सरकारी प्राथमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गई हैं, 21,350

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, 6,995 माध्यमिक विद्यालयों और 6,223 उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है।

दिनांक 17 मई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के एक भाग के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई, जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है ताकि देश भर में शिक्षा तक बहु-विध पहुँच सुनिश्चित की जा सके। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र(यूटी) अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों के उपयोग, निगरानी और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। पीएम ई-विद्या में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों (एबी)/भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों को आवंटित 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं, ताकि वे कक्षा 1-12 के छात्रों को उनकी आवश्यकतानुसार विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें।

ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) राष्ट्र का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री के साथ-साथ सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड वाली सक्रिय पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) उपलब्ध कराता है। दीक्षा में भागीदार के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ स्वायत्त निकायों (एबी) ने स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.69 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और उसमें योगदान दिया है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 564.05 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए जा चुके हैं। हितधारकों के पास दीक्षा पर 300 से अधिक वर्चुअल लैब तक पहुँच है।

केंद्रीय बजट 2025 में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत बीएसएनएल के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने का प्रावधान शामिल है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की अध्ययन योजना के अनुसार, छात्र कक्षा 9वीं से 12वीं तक कंप्यूटर आधारित विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से डिजिटल कौशल का आधारभूत ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत, छात्र अपनी कंप्यूटर साक्षरता बढ़ाने के लिए छह मॉड्यूल, अर्थात् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, कोडिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, संवर्धित/आभासी वास्तविकता (एआर/वीआर) और डिजिटल नागरिकता में से किसी एक का अध्ययन कर सकते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने बोर्डों के माध्यम से कंप्यूटर आधारित विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है।

शिक्षा मंत्रालय के तहत एनसीईआरटी के राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र द्वारा आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में देश भर में कक्षा 3, 6 और 9 के 21 लाख से अधिक छात्रों का मूल्यांकन किया गया, जो विशेष रूप से कंप्यूटर साक्षरता पर केंद्रित नहीं था, तथापि, इसने डिजिटल पहुंच पर प्रासंगिक डेटा एकत्र किया जिसे https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en से एक्सेस किया जा सकता है।

*****